



नेत्रदान के बाद भगवान जगन्नाथ ने दिए दर्शन

RANCHI : गुरुवार को ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का नेत्रदान किया गया। इस दौरान नेत्रदान के बाद भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। यह अवसर हर वर्ष केवल एक बार आता है, जब भगवान एकांतवास के बाद भक्तों के समक्ष सजीव प्रतीक के रूप में प्रकट होते हैं। मंदिर समिति के अनुसार, 11 जून को देव स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान एकांतवास में चले गए थे। इस दौरान उन्हें अस्वस्थ माना जाता है और किसी को दर्शन नहीं देते। लेकिन, नेत्रदान के दिन विशेष पूजा और अनुष्ठानों के बाद भगवान भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं। इस दिन को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है।

हॉस्पिटल में इलाज कर रहे डॉक्टरों से ली स्वास्थ्य की जानकारी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, शिबू सोरेन का जाना हाल

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड के झामुमो के संरक्षक शिबू सोरेन बीते कुछ दिनों से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सर गंगाराम अस्पताल पहुंचीं और शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चिकित्सकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उनके स्वास्थ्य के बारे में हेमंत सोरेन से भी जानकारी ली। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी वहां मौजूद थे।

फिलहाल दिशोम ग्यूरु की तबीयत बताई जा रही स्थिर



आज रांची लौट सकते हैं सीएम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं। पहले संभावना बताई जा रही थी कि वह गुरुवार शाम रांची लौट सकते हैं, लेकिन गुरुजी की स्थिति को देखते हुए अब उनका रांची लौटना शुक्लवार सुबह संभावित है।

डॉक्टरों की टीम लगातार कर रही निगरानी

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, शिबू सोरेन की तबीयत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। चिकित्सकों का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही उनकी स्थिति को लेकर कोई ठोस जानकारी दी जा सकेगी।

SHARE	
सेंसेक्स	: 83,755.87
निफ्टी	: 25,549.00
SARAF	
सोना	: 9,250
चांदी	: 120.00
(नोट : सोना 22 केरेट प्रति ग्राम)	

BRIEF NEWS

नहीं रहे चर्चित हास्य कवि डॉ. सुरेंद्र दुबे

RAIPUR : गुरुवार को छत्तीसगढ़ से एक दुःखद खबर सामने आई। अपनी हास्य कविताओं और तीखे व्यंग्य से देशभर के लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, डॉ. दुबे का रायपुर के एक निजी अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था। गुरुवार दोपहर हृदय गति रुक जाने के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे छत्तीसगढ़ सहित देश के साहित्यिक और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कवि डॉ. सुरेंद्र दुबे को जमशेदपुर व झारखंड के अन्य शहरों के लोग व खासकर साहित्य प्रेमी कभी नहीं भूलेंगे। यहां कई हास्य कवि सम्मेलनों में जमशेदपुरवासियों को कवि सुरेंद्र दुबे को सुनने का अवसर मिल चुका है। उनके चुटीले अंदाज, उनकी कविताएं आज भी यहां के साहित्य प्रेमियों की जुबां पर हैं।

डीजीपी अनुराग गुप्ता को मिलेगी प्रोविजनल पे-स्लिप

RANCHI : झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे-स्लिप मिलेगी। महालेखाकार ने इससे संबंधित आदेश और पे-स्लिप जारी कर दिया है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि कोर्ट का फैसला अपर अनुराग गुप्ता के खिलाफ आता है, तो वेतन की गिरावणी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अनुराग गुप्ता की सेवा को 30 अप्रैल 2025 तक ही माना है। इसके बाद से उन्हें सेवानिवृत्त माना जा रहा है। मंत्रालय ने इससे संबंधित पत्र भी झारखंड सरकार को लिखे थे। इस पत्र के जवाब में राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को बताया है कि डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की गई है।

पहलगाम आतंकी हमले को नजरअंदाज करने का राजनाथ ने उठाया मुद्दा

एससीओ डॉक्यूमेंट पर भारत का सिग्नेचर करने से इनकार

NEW DELHI @ PTI :

गुरुवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले को नजरअंदाज करने और पाकिस्तान समर्थित सीमा पर आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करने को लेकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मामले से परिचित व्यक्तियों ने बताया कि एससीओ आम सहमति के तहत काम करता है, लिहाजा वक्तव्य का समर्थन करने से सिंह के इनकार के परिणामस्वरूप एससीओ रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य जारी किए बिना ही समाप्त हो गया। जानकारों ने कहा कि मसौदा वक्तव्य में न तो पहलगाम आतंकवादी हमले का उल्लेख किया गया और न ही सीमा पर आतंकवाद को लेकर भारत के रुख का जिक्र किया गया।

रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन संयुक्त वक्तव्य जारी किए बिना ही हो गया समाप्त

सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत के रुख का संयुक्त वक्तव्य में नहीं किया गया था जिक्र
आतंकवाद को समर्थन देने के लिए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को किया ब्लैकमेल
अपने अधिकार का इस्तेमाल कर आतंकियों के खिलाफ भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर
चीनी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हॉटलाइन फिर से शुरू करने पर हुई चर्चा



दोहरे मानदंडों के लिए नहीं होनी चाहिए कोई जगह

सम्मेलन में अपने संबोधन में सिंह ने सीमा पार आतंकवाद को लगातार समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की तथा आतंकवाद के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये खतरे सभी देशों के सामने हैं और इनसे निपटने के लिए पारदर्शिता, आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित एकीकृत प्रयासों की जरूरत है।

चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता

बुधवार को किंगदोमो पहुंचे रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में बदलाव की व्यापक रूपरेखा रखी और एससीओ सदस्य देशों से आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होने तथा दोहरे मानदंडों को त्यागने का आग्रह किया। सम्मेलन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून भी शामिल हुए। सिंह ने कहा, शांति व समृद्धि आतंकवाद और सरकार से इतर तत्वों तथा आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार देने की नीति साथ नहीं चल सकती। उन्होंने कहा, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।

राजधानी सहित आसपास के इलाकों में सुबह से ही रुक-रुक कर होती रही वर्षा झारखंड में सामान्य से 92 प्रतिशत अधिक बारिश

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड में अब तक सामान्य से अधिक मानसून की बारिश दर्ज की गई है। राज्य में अब तक सामान्य से औसत 92 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार एक जून से 25 जून तक झारखंड में 139.9 मिमी के मुकाबले 268.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश राजधानी रांची में दर्ज की गई है। यहां सामान्य से 231 मिमी बारिश

139.9 मिमी के मुकाबले 268.7 मिमी रिकॉर्ड की गई है वर्षापात



29 जून तक बारिश होने की संभावना

झारखंड के जिन जिलों में अब तक अच्छी बारिश दर्ज की गई है उनमें लातेहार में 130 के मुकाबले 422.6 मिमी, लोहरदगा में 146.2 की तुलना में 388.2, रामगढ़ में 147.2 के मुकाबले 357.4, सरायकेला-खरसावा में 157.9 की तुलना में 400 मिमी, खुर्दी में 150.9 मिमी की तुलना में 287.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसर,

राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में गुरुवार को भी सुबह से रुक-रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में 29 जून तक बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं भारी बारिश होने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है।

रिकार्ड की गई है, जबकि सबसे कम बारिश राज्य में देवघर जिले में हुई है। यहां पर सामान्य से 14

प्रतिशत कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। रांची में 146.4 के मुकाबले 484.4 मिमी बारिश दर्ज की गई

है। वहीं देवघर में 136.8 मिमी की तुलना में 117.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है।

बड़ी उपलब्धि गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद का खुला रास्ता

कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किए जाएंगे सूक्ष्म जहरीले कण

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

तकनीकी दृष्टि से बीमारियों के इलाज के लिए वैज्ञानिक रोज नए अनुसंधान कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में ऐसे जहरीले कण पाए जाते हैं, जो बड़ी बीमारियां पैदा करते हैं। इनकी दशा और प्रभाव का आकलन अब तक बहुत मुश्किल था। हाल में वैज्ञानिकों ने हवा में घुले खतरनाक ऐसे सूक्ष्म कणों की निगरानी के लिए एक नई कंप्यूटर तकनीक विकसित की है, जो बेहद बारीकी से यह पता लगाएगी कि ये कण कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब तक इन नन्हें कणों के व्यवहार को समझना मुश्किल था, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि शरीर के अंदर तक पहुंच जाते हैं और हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। नई तकनीक की मदद से अब वैज्ञानिक यह बहुत तेजी और सटीकता से जान पाएंगे कि ये कण हवा में कैसे तेरते हैं, किन रास्तों से शरीर तक पहुंचते हैं और वहां जाकर कैसे असर डालते हैं। जर्नल ऑफ कम्यूटेशनल फिजिक्स में प्रकाशित एक शोध अध्ययन में कहा गया है कि वर्तमान में जिस जांच प्रक्रिया में हफ्तों लगते हैं, उन्हें कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकता है।

अब तक इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के प्रभाव को समझना था मुश्किल हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं ये कण

➤ नई तकनीक यह पता लगाएगी कि कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ते हैं ये पार्टिकल

➤ जर्नल ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स में विस्तार से प्रकाशित की गई है शोध संबंधी रिपोर्ट



वायु प्रदूषण की हो सकेगी सटीक निगरानी

➤ कणों के हवा में तेरने व मानव शरीर तक पहुंचने की स्थिति का किया गया है विश्लेषण

धीरे-धीरे सेहत पर पड़ता है घातक असर
शोधकर्ताओं का कहना है कि हवा में जो कण होते हैं, वे इतने छोटे होते हैं कि हमारी नाक या शरीर की सामान्य सुरक्षा को पार करके सीधे फेफड़ों और खून में घुस सकते हैं। ऐसे कणों का असर धीरे-धीरे होता है, लेकिन बहुत घातक होता है। इन्हें देखकर यह जान पाना कि वे कैसे फैलते हैं, अब तक आसान नहीं था। इस नई तकनीक से अब यह काम मुमकिन हो सकेगा। यह तकनीक वायु प्रदूषण की सटीक निगरानी करेगी।

अहमदाबाद प्लेन क्रेश



ब्लैक बॉक्स का डेटा किया गया रिकवर

AHMEDABAD : अहमदाबाद में 12 जून को क्रेश हुए एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सरकारी बयान में गुरुवार को बताया गया कि डेटा डाउनलोड हो गया है। मेमोरी मॉड्यूल का एक्सेस भी मिल गया है। अब जांच एजेंसी ब्लैक बॉक्स से रिकवर हुए डेटा का विश्लेषण (एनालिसिस) करेगी। इससे हादसे के कारणों का पता चलेगा।

● मेमोरी मॉड्यूल को भी किया गया एक्सेस, इससे हादसे के कारणों का पता चलेगा। इससे पहले 24 जून को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया था कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश नहीं भेजा जा रहा। इसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन

ब्यूरो (एआईबी) कर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, क्रेश प्लेन से दो ब्लैक बॉक्स (सीडीआर और डीएफडीआर) सेट मिले हैं। इनमें हादसे के समय पायलट की बातचीत और विमान की तकनीकी जानकारी का रिकॉर्ड मिलेगा। पहला सेट 13 जून को और दूसरा 16 जून को बरामद किया गया। अहमदाबाद में 12 जून को लॉन्ग जाने वाली एयर इंडिया की प्लाइट एआई-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रेश हो गई थी। इधर, विशेष प्रमंडल लोहरदगा के नाजिर वरुण कुमार को रांची एसीबी की टीम ने

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे शुभांशु शुक्ला सहित चार अंतरिक्ष यात्री



NEW DELHI @ PTI :

गुरुवार को अंतरिक्ष यान ड्रैगन के अंतरिक्ष प्रयोगशाला से जुड़ने के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पहुंच गए। अंतरिक्ष यान उस समय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा जब यह भारतीय समयानुसार अपराह्न 4:01 बजे उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था। यह पहली बार है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री आईएसएस की यात्रा पर गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा, गुरुवार को सुबह 6:31 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4:01 बजे) एक्सओम मिशन-4 के तहत स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। नासा के एक लाइव वीडियो में अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष स्टेशन के पास आते हुए दिखाया गया और डॉकिंग प्रक्रिया भारतीय समयानुसार

भारतीय समयानुसार अपराह्न 4:01 बजे उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरते वक्त आईएसएस से जुड़ा ड्रैगन

➤ यह पहली बार है, जब आईएसएस की यात्रा पर गया कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री

➤ नासा के लाइव वीडियो में अंतरिक्ष स्टेशन के पास आते दिखा अंतरिक्ष यान

➤ संचार और ऊर्जा संपर्क स्थापित होने के साथ ही पूरी हो गई डॉकिंग प्रक्रिया

अपराह्न 4:15 बजे पूरी हुई। अंतरिक्ष यान और आईएसएस के बीच संचार और ऊर्जा संपर्क स्थापित होने के साथ ही डॉकिंग प्रक्रिया पूरी हो गई।

शुक्ला एक्सओम-4 के लिए मिशन पायलट

अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन मिशन कमांडर हैं और शुक्ला एक्सओम-4 मिशन के लिए मिशन पायलट हैं। इनके अलावा, हमारी के अंतरिक्ष यात्री टिवोर कपू एवं पोलैंड के रलावोज उजान्स्की-विन्स्कीएरी एक्सओम-4 मिशन का हिस्सा हैं। लखनऊ में जन्मे 39 वर्षीय शुक्ला अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले

दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इससे 41 साल पहले भारत के राकेश शर्मा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सैल्यूट-7 अंतरिक्ष स्टेशन के तहत कक्षा में आठ दिन रहे थे। पोलैंड के इंजीनियर रलावोज एक मिशन विशेषज्ञ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री हैं।

एंटी करप्शन ब्यूरो ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई धनबाद और लोहरदगा में रिश्वत लेते 2 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार

PHOTON NEWS TEAM :

गुरुवार को झारखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 2 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक कर्मचारी को धनबाद से गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरे को लोहरदगा से। धनबाद में एलआरडीसी कार्यालय में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटर अनीश कुमार को एसीबी की टीम ने 15 हजार रुपये रिश्वत गिरफ्तार किया है। अनीश पर आरोप है कि वह एक व्यक्ति से जमीन से संबंधित मामले में घूस मांग रहा था। इधर, विशेष प्रमंडल लोहरदगा के नाजिर वरुण कुमार को रांची एसीबी की टीम ने



● कंप्यूटर ऑपरेटर अनीश कुमार 15 हजार रुपये घूस लेते अरेस्ट

● विशेष प्रमंडल का नाजिर ₹4 हजार लेते धराया

रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने उसे 4 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है।



संतरा और नींबू- विटामिन सी के लिए संतरा, मौसमी और नींबू को भी बहुत अच्छा माना जाता है। सिट्रिक फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है। रोजाना एक मीडियम संतरा खाने से शरीर में 70 मिलीग्राम विटामिन सी पहुंचता है। आप संतरा का जूस भी पी सकते हैं। वहीं 100 ग्राम नींबू खाने से भी करीब 50-60 मिलीग्राम विटामिन सी शरीर को मिलता है।

धनिए का पानी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले धनिए के बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगोरकर रखें। अब आप अगली सुबह इस पानी को छानकर पी सकते हैं। इसके अलावा धनिए की पत्तियों को पानी में बॉइल करके भी कंज्युम किया जा सकता है।

हेल्थ एससपर्ट्स के मुताबिक विटामिन बी12 की अधिकता, आपके शरीर के साथ-साथ आपकी त्वचा पर भी बुरा असर डाल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस विटामिन की अधिकता की वजह से आपको मुँहासों, खुजली और रेश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके शरीर में इस विटामिन की अधिकता है, तो आपको अपने डाइट प्लान में विटामिन बी12 से भरपूर खाने-पीने की चीजों को शामिल करने से बचना चाहिए।

आपातकाल का काला अध्याय : एक त्रासद स्मृति



अर्जुन राम मेघवाल

आपातकाल के 21 महीनों ने भारतवासियों की संवैधानिक विरासत की समझ को झकझोर कर रख दिया था। इंदिरा गांधी ने 25 जूनझु 1975 की रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सादे कागज पर (बिना कैबिनेट की सहमति और आधिकारिक लैटरहेड के) अनुच्छेद 352 के तहत ह्हाआंतरिक अशांति' के आधार पर देश में आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी। यह देश की संवैधानिक शासन व्यवस्था पर सीधा प्रहार था

पाचास वर्ष पूर्व, 25 जून 1975 का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर देश में आपातकाल की घोषणा की, जिसने देश के संविधान की आत्मा को कुचल कर रख दिया। इसके बाद देश में आपातकाल के 21 महीनों ने भारतवासियों की लोकतंत्र, सरकार और संवैधानिक विरासत की समझ को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। यह वह क्षण था जब ह्हालोकतंत्र की जननीहू कहें जाने वाले भारत को तत्कालीन तानाशाही सरकार के अविवेकपूर्ण और क्रूर निर्णय से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती गांधी को 1971 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने का दोषी ठहराते हुए उनका लोकसभा के लिए निर्वाचन अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग बढ़ती गई और इसी बीच इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक सादे कागज पर (बिना कैबिनेट की सहमति और आधिकारिक लैटरहेड के) अनुच्छेद 352 के तहत ह्हाआंतरिक अशांतिहू के आधार पर देश में आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी। यह देश की संवैधानिक शासन व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। अगले दिन 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक में यह विषय औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया।

इस कदम से देश में कांग्रेस के तानाशाही शासन की शुरुआत हुई। जनता को संविधान से मिली आजादी रातों-रात समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और देश के भीतर आने-जाने की स्वतंत्रता एक झटके में खत्म कर दी गई। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला अनुच्छेद 21 निरर्थक हो गया। सबसे दुखद यह था कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के जिस अनुच्छेद 32-जो नागरिकों को न्यायालय जाने का अधिकार देता है— को संविधान की ह्हाआत्माहू कहा था, उसे भी निरस्त कर दिया गया। आपातकाल के दमनचक्र के पहले शिकार व विपक्षी नेता बने जिन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया था। हजारों लोगों को कठोर मीसा(मेंटनेंस ऑफ इंटरनल सेक्युरिटी एक्ट) और भारत रक्षा अधिनियम (डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट) के तहत जेल में डाला गया, इसके बाद धीरे-धीरे देश का हर नागरिक देश पर थोपे गए आपातकाल के इस काले अध्याय के घावों का अनुभव करने लगा था।

इस कालखंड में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीन स्तंभ जैसे जाने वाले कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पर अभूतपूर्व हमला हुआ। इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों के दश आज भी देश की जनता के मानस पटल पर एक भयावह स्मृति के रूप में अंकित है। भरे 90 वर्षीय दादा जी को उसी दौर में अपने रोजमर्रा के काम के दौरान गांवों की देखभाल करते हुए उंगली में गहरी चोट लग गई थी जिसके इलाज के लिए उन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अस्पताल में उन्हें पता चला कि नसबंदी लक्ष्यों को



पूरा करने के सरकारी दबाव के चलते डॉक्टर उन्हें जबरदस्ती नसबंदी के लिए तैयार कर रहे हैं। इस अमानवीय स्थिति को भांपते हुए भरे दादा जी अस्पताल से भाग निकले और बिना इलाज के वापस लौट गए। इस प्रकार जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले अस्पताल भयावह कष्ट देने वाले केन्द्र के रूप में बदल गए थे। हालांकि वे बच गए, लेकिन उस भयावह अनुभव ने पूरे समुदाय को गहरे डर और सदमे से भर दिया था। दुर्भाग्यवश 1975 से 1977 के बीच एक करोड़ से अधिक लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई- यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय बन गया।

उस काले दौर में प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग केवल एक परिवार के हित में किस हद तक किया गया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 24 मार्च 1976 को संजय गांधी की बीकानेर यात्रा थी। न तो उनके पास कोई संवैधानिक पद था, न ही वे राजकीय अतिथि थे, फिर भी उनके स्वागत में सरकारी संसाधनों की खुलकर बबांदी की गई। उस समय मैं डाक एवं तार विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर था और मुझे यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि रैली में विशिष्ट लोगों के लिए बनाए गए मंच के नीचे अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन लगाने के आदेश दिए गए—जबकि ऐसी व्यवस्था केवल प्रधानमंत्री के लिए की जाती है। यह घटना सरकारी तंत्र पर संजय गांधी के न केवल अनुचित प्रभाव को दर्शाती है, बल्कि यह बताती है कि कैसे तत्कालीन सरकारी तंत्र को व्यक्तिगत और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु काम करने के लिए विवश कर दिया गया था।

ऐसे दौर में जबकि सामान्य जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, तब जनता के पैसों से किए गए ऐसे दिखावे संविधान की गरिमा के प्रति घोर उपेक्षा और सरकार के नैतिक पतन को दर्शाते हैं। वह भारत में लोकतंत्र के हनन का सबसे बुरा दौर था।

आपातकाल के दौरान संविधान में सरकार के तानाशाही रवैये की पुष्टि करने वाले संशोधन किए गए जिससे लोकतंत्र की आत्मा को गहरी चोट पहुंची और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। संविधान में 38वां संशोधन करके आपातकाल की घोषणा

की समीक्षा करने में न्यायालय की भूमिका समाप्त कर दी गई तथा अध्यादेश जारी करने के मामले में राष्ट्रपति व राज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिए गए। इसके तुरंत बाद 10 अगस्त 1975 को लागू किए गए 39वें संविधान संशोधन द्वारा से न्यायालयों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष जैसे उच्च पदों से जुड़े चुनावी मामलों की न्यायिक समीक्षा करने से रोक दिया गया। यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध दिए गए निर्णय के बाद श्रीमती गांधी को न्यायालय के प्रति जबाबदेही से बचाने की एक सोची-समझी चाल थी। ऐसा करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जानबूझकर कुचला गया। इस संविधान संशोधन के बाद ह्हाए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लाहू के मामले की काफी चर्चा हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के निर्णय को सही ठहराया था। उस मामले में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ही खन्ना ही न्यायाधीश थे जिन्होंने उस निर्णय से अपनी असहमति जताई थी और नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। बाद में श्री खन्ना को वरिष्ठतम होने के बावजूद भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया और ऐसा करना न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा प्रहार था। आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी की सत्तालोलुपता का एक दूसरा उदाहरण 42वें संविधान संशोधन करना था जिसके माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया। ऐसा करके लोकतंत्र में जनादेश की गरिमा को और अधिक कम किया गया और आम चुनाव कराए बिना सरकार के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देश्यिका में तीन नए शब्द समाजिक, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए और ऐसा करके मूल संविधान से छेड़छाड़ की गई। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा 48 अध्यादेश जारी किए गए और इन्हें पारित करने में संसद में चर्चा, विधेयकों की जांच-पड़ताल और संशोधन करने की प्रक्रिया की अनदेखी की गई। आपातकाल के बाद गठित शाह आयोग ने इतिहास के उन काले दिनों के दौरान ढेर सारे लोगों को बेवजह नजरबंद करने, गरीबों की जबरन नसबंदी करने और सत्ता के संस्थागत रूप से दुरुपयोग की

युद्ध में संयम और धैर्य जरूरी

लॉन्च की गई 30 से अधिक टॉमहॉक मिसाइलें शामिल थीं। सेटेलाइट इमेज से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परमाणु सुविधा नष्ट हो गई है, विकिरण बाहर नहीं आ सकता क्योंकि यह बहुत गहरे भूमिगत में था। यह हमला पहली बार था जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बंकर-बरिंटा बम, जीबीयू-57 मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (एमओपी) का इस्तेमाल किसी ऑपरेशनल संघर्ष में किया था। इस अभियान में फोर्ड और नतांज में दो यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं और इस्फ़हान में एक सुविधा को निशाना बनाया गया, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित कई गतिविधियों का संचालन करती है। नतांज और फोर्ड ईरान में एकमात्र परिचालन संवर्धन सुविधाएं हैं। अमेरिका ने नातान्ज और फोर्ड पर एमओपी से सुसज्जित बी-2 बमवर्षकों से हमला किया तथा केवल इस्फ़हान पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। फोर्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ईरानी शहर कोम से 29 किलोमीटर उत्तर में एक पहाड़ के भीतर स्थित, फोर्ड यूरेनियम संवर्धन सुविधा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भीतर एक अत्यधिक संरक्षित और रणनीतिक रूप से केंद्रीय स्थल है। इसकी भूमिगत स्थिति संभावित हवाई बमबारी के

खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, एक डिजाइन विकल्प जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका संकेत देता है। यह सुविधा लगभग 54,000 वर्ग फीट में फैली हुई है और माना जाता है कि इसमें 3,000 सेंटीप्यूज हैं। 2015 की संयुक्त व्यापक योजना की शर्तों के तहत, ईरान को फोर्ड में संवर्धन गतिविधियों का संचालन करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। बी-2 बमवर्षक विमान जमीन से 200 फीट नीचे तक बहुत ही आक्रामक होता है, चाहे वह स्टील हो या कंक्रीट अब जबसिजफायर की घोषणा हुई है तो शांति से काम लेना चाहिएदूसरे देश ईरान पर युद्ध के लिए दबाव बना रहे हैं कि ईरान को परमाणु बम मिल जाएया जिससे तनाव की माहौल बन रहा है। ट्रंप ने जो भी कहा है कि इजरायल उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगा। ईरान को परमाणु बम मिलने पर पूरी तरह से ईरान आक्रामक पूरी तरह से आक्रामक हो गया हैजिससे आम जनता को उत्सुकान हो रहा है 1960 के दशक की शुरुआत में, राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी को एक जटिल भू-राजनीतिक स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसने उनके प्रशासन को इजरायल की गुप्त परमाणु महत्वाकांक्षाओं में उलझा दिया। इस संघर्ष के केंद्र में

इजरायल का परमाणु हथियार कार्यक्रम था, जिसका जेकेएफ (खन्नहू) ने कड़ा विरोध किया, खासकर यह पता चलने के बाद कि देश अत्यधिक संदिग्ध परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरेनियम प्राप्त कर रहा था। इजरायल की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और चुराए गए यूरेनियम का मामला दशकों से साजिश और संदेह का स्रोत रहा है, कुछ विशेषज्ञों ने तो यह भी सुझाव दिया कि इजरायल के परमाणु विकास के प्रति केंनेडी के विरोध ने 1963 में उनकी दुष्प्रद हत्या में योगदान दिया हो सकता है। परमाणु प्रसार पर केनेडी की स्थिति अडिग थी। उन्होंने परमाणु हथियारों के प्रसार को वैश्विक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा, और इजरायल की परमाणु महत्वाकांक्षाएं उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय थीं। राष्ट्रपति ने इजरायल सरकार पर अपने गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ने के लिए दबाव डालने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (कभएच) द्वारा इजरायल की डिमाना परमाणु सुविधा के संस्थागत, नियमित निरीक्षण के लिए दबाव डाला। यह न केवल एक कूटनीतिक चिंता थी बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था।



संजय गोस्वामी

पेंटागन ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान पर जो अभियान चलाया था, उसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। यह 21-22 जून, 2025 की मध्यरात्रि के आसपास ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के नेतृत्व में किए गए गुप्त सैन्य हमले का कोडनम है।हसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद करना था । जो लगभग सफल रहा है इस समन्वित हमले में 125 से अधिक सैन्य विमान शामिल थे, जिनमें बी-2 स्टील्थ बॉम्बर, 14 जीबीयू-57 बंकर-बस्टर बम की तैनाती और फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी पनडुब्बियों से



निर्मल रानी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों नई दिल्ली में एक पूर्व आईएएस अधिकारी द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक वाक्य बोलकर राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई विवाद को जन्म दे दिया। गृह मंत्री ने कहा कि इस दश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज निर्माण और दूर नहीं है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अमित शाह के इस बयान की काफी तीखी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने अंग्रेजी को रोजगार परक भाषा बताने तो कुछ का मानना था कि आत्मविश्वास के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जबकि कुछ नेताओं ने इस बयान को भारत की भाषाई बहुलता को कमजोर करने और हिंदी थोपने के प्रयास की नजरों से देखा। आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत सरकार के ही अनेक मंत्री ऐसे हैं जो धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलते हैं। कई प्रमुख मंत्री हैं तो ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी में प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए ही जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में अत्यंत धाराप्रवाह हैं। वे जेएनयू से अर्थशास्त्र की डिग्री धारक है। वित्तीय नीतियों पर वैश्विक मंचों जैसे जी 20 पर उनके भाषण उनके अंग्रेजी बोलने के कौशल को दर्शाते हैं। इसी तरह

विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, जो पूर्व राजनयिक भी रहे हैं, अंग्रेजी में असाधारण रूप से धाराप्रवाह हैं। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कूटनीतिक चर्चाओं में प्रायः अंग्रेजी का व्यापक उपयोग करते हैं। इसी प्रकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अंग्रेजी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और निवेश से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में उनकी धारा प्रवाह अंग्रेजी उनकी काबिलियत में चार चाँद लगाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, यह भी पूर्व राजनयिक हैं तथा अंग्रेजी में उत्कृष्ट संवाद का कौशल रखते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसी तरह नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जोकि हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से शिक्षित हैं अंग्रेजी में अत्यंत धाराप्रवाह हैं और संसद व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसका उपयोग करते हैं। अमेरिका में शिक्षित और प्रशिक्षित चिकित्सक ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. प्रेमसांनी, जो हैं, अंग्रेजी में पूरी तरह से पारंगत हैं। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं विशेषकर दक्षिण भारत के अधिकांश सांसद व मंत्री अंग्रेजी में संवाद करते हैं।

ऐसे में अमित शाह का यह कहना कि ऐसा समाज निर्माण और दूर नहीं है कि इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी,इसका अर्थ निकालना व इसका विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। क्यों शर्म आयेगी अंग्रेजी बोलने वालों को ? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब विदेश जाते हैं तो प्रॉप्रेटर पर ही सही परन्तु अंग्रेजी में ही भाषण देकर भारत का पक्ष रखते हैं ? कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाइये ,यदि आप क्षेत्रीय भाषा बोल पाने में असमर्थ हैं तो अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है जो एक दूसरे राज्य के लोगों

के मध्य संवाद स्थापित करने का सुगम माध्यम बनती है। देश ही नहीं लगभग पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा विभिन्न देशों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। आज गूगल मंत्री अमित शाह के दर्जनों मंत्रिमंडलीय सहयोगियों,सांसदों व अधिकारियों व राज्य स्तरीय भाजपा नेताओं की संतानें अमेरिका,ब्रिटेन,ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य कई देशों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। जाहिर है राष्ट्राध्यक्षों की यह संतानें वहां संस्कृत या हिंदी माध्यम से पढ़ने के लिये नहीं गयी हैं। बल्कि यह वहां पढ़कर अंग्रेजी भाषा में ही पारंगत होंगी। तो क्या आने वाले कल को इन्हें भी अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी ?

इसमें कोई संदेह नहीं कि क्षेत्रीय भारतीय भाषाएं भारतीय संस्कृति के आभूषण के समान हैं। परन्तु अदालत से लेकर संसद व दूतावासों तक व मेडिकल व विज्ञान शास्त्र में खासकर प्रयुक्त होने वाली अंग्रेजी भाषा को शर्म वाली भाषा तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। गृह मंत्री के अनुसार यदि शर्म ही आने की संभावना है तो कम से कम अपनी सरकारी योजनाओं का मेक इन इंडिया,डिजिटल इंडिया,स्टार्टअप इंडिया जैसा अंग्रेजी नाम तो न रखते ? इस सम्बन्ध में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सीखना आर्थिक रूप से उपयोगी है और इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने शाह के इस बयान को शर्म की भाषाई बहुलता पर हमला बताया। कांग्रेस ने तो इसे सांस्कृतिक आतंकवाद का हिस्सा बताया और कहा कि अंग्रेजी वैश्विक संदर्भ में भारत के युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके ने भी शाह के बयान को हिंदी थोपने की एक और कोशिश के रूप में देखा है । डीएमके ने तर्क दिया कि अंग्रेजी भारत की भाषाई विविधता को जोड़ने वाली कड़ी है और इसे कमजोर करना देश की एकता

भयावह तस्वीर प्रस्तुत की थी।

इस तानाशाही शासन के दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस का भी गला घोट्टा गया। जो पत्रकार सहानुभूतिपूर्वक विपक्षी नेताओं की खबरों को प्रकाशित कर रहे थे उन्हें जेल भेजा गया। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सम्मानित नवजीवन प्रेस को जब्त कर लिया गया, यह स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत पर सीधा हमला था। चार प्रमुख समाचार एजेंसियों—प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती—को जबरदस्ती मिलाकर समाचार नामक एक संस्था बना दी गई। आज, 50 वर्ष बाद, कांग्रेस की दोहरी मानसिकता उजागर हो चुकी है—एक ओर वे ह्रासंविधान बचाओ यात्राहू के नाम पर भ्रम फैलाते हैं, दूसरी ओर अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संविधान के अपमान पर चुप रहते हैं। श्री राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को लोकसभा में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इस भयावह काले अध्याय के बारे में गर्व से कहा, ह्हाआपातकाल में कुछ भी गलत नहीं था ह्हा यह कथन यह दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए परिवार और सत्ता सर्वोच्च है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय मात्र 25 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने साहसपूर्वक इस तानाशाही शासन का विरोध किया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग नामों से भूमिगत रहकर गुप्त बैठकों का आयोजन किया और आपातकाल विरोधी साहित्य व पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं वितरण में यत्न से जुटे रहे। जब आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण इसे भूमिगत होना पड़ा तब मोदी जी ने गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव के रूप में लोकतंत्र की रक्षा हेतु अहम भूमिका निभाई।

विगत में संविधान की आत्मा पर किए गए गहरे प्रहार की याद में मोदी सरकार ने 11 जुलाई 2024 को जारी की गई गजट अधिसूचना के माध्यम से 25 जून का दिन ह्रासंविधान हत्या दिवसहू के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन उस विश्वासघात की याद दिलाता है जो आपातकाल के दौरान संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ किया गया था। यह प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र का जगारूक प्रहरी बनने की प्रेरणा देता है, ताकि हम इतिहास के उन काले अध्यायों से सीख प्राप्त करें और हम काफी यत्न से प्राप्त की गई स्वतंत्रता के मूल्यों की रक्षा कर सकें। देश में आपातकाल का काला अध्याय 50 वर्ष पहले समाप्त हो गया है लेकिन वह भयावह दौर हमें इस बात की याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें हमेशा सजग प्रहरी बने रहने की आवश्यकता है। हमारा संविधान पीढ़ियों की कुर्बानियों, बुद्धिभार, आशाओं और आकांक्षाओं का परिणाम है। आज जब भारत हमारे आंदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ह्हाविकसित भारत @ 2047हू की ओर अग्रसर है, तो हमें एक जीवंत और विकसित लोकातांत्रिक राष्ट्र के निर्माण हेतु अपने नागरिकों के संकल्प से सामर्थ्य प्राप्त कर राष्ट्र की महत्वाकांक्षा की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को एक बार फिर से दोहराने की आवश्यकता है।

(*केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार*)

संपादकीय

खतरे की घंटी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्त्राइल-ईरान के दरम्यान अस्थायी युद्धविराम के राजी होने के ऐलान के कुछ देर बाद ही हमले पुनः चालू हो गए। इरानी सेना का आरोप है कि ऐलान के कुछ देर बाद ही इस्त्राइल की तरफ से हवाई हमलों की बौझार शुरू हो गई जिसमें चार की जान गई जबकि इस्त्राइल का कहना है कि ईरान की तरफ से दो मिसाइलें दागी गई जिन्हें उसने निष्क्रिय कर दिया। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि इस्त्राइल अपने लड़ाकू विमान वापस बुलाएगा और वह ईरान में शासन परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। परंतु हमलों के जारी रहने के बाद दर शाम अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है जबकि व्हाइट हाउस ने खंडन करते हुए इसे पूरी तरह गलत कहते हुए इसे ट्रंप को नीचा दिखाने का प्रयास बताया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए हैं। मगर ज्यादातर सेंट्रोप्यूज सुरक्षित हैं। शीर्ष अधिकारी पहले ही दावा कर रहे थे कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। ट्रंप इसे फेक न्यूज बता रहे हैं। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विट्कोफ ने एक न्यूज चैनल से कहा, यह देशद्रोह है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमलों के बावजूद इस्त्राइल और ईरान के मीडिया अहमेल-अपने देशों की विजय का दावा कर रहे हैं। ईरान पहले ही अमेरिका को चेता चुका था। तनाव की स्थिति में कहना जल्दबाजी होगी कि खतरा टल गया है। इराक, इहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, कतर जैसे देशों में अपने सैन्य अड्डे इरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में आने के कारण अमेरिका के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। वास्तव में यदि दोनों पक्ष युद्धविराम का उल्लंघन करने पर तुले हैं तो यह योजनाबद्ध प्रतिशोध वैश्विक चेतावनी का सूचक है। ट्रंप के दृढ़ सोशल पर लिखने, कि इस्त्राइल बम मत गिराओ इसे उल्लंघन करना जाएगा, को इतिहास में अमेरिका की तरफ से सबसे कड़ी फटकार मानी जा रही है। परंतु इस सारे मसले में अमेरिका को स्वार्थ त्याग कर स्पष्ट रूप से विश्व शांति के प्रयास करने चाहिए। अगर वह महाशांति है तो चीन/रूस भी अपने कदम पीछे लौटाने की बजाए संघर्ष को प्राथमिकता दें। ट्रंप के आलोचक उनके इस कदम को न सिर्फ जोखिम भरा कह रहे हैं, बल्कि युद्ध शक्ति अधिनियम का उल्लंघन भी ठहरा रहे हैं। बेशक, खतरा टला नहीं है।

चिंतन-मनन

प्रोध का जवाब प्रोध नहीं

एक बार एक ब्राह्मण ने महात्मा बुद्ध को अपने घर आकर, भोजन करने का निमंत्रण दिया। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ब्राह्मण ने उन्हें किसी अन्य मकसद से वहां बुलाया था। ब्राह्मण उनकी निंदा करने लगा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ब्राह्मण के वचनों के बार चुपचाप सहते रहे। अंत में बुद्ध ने कहा,हे ब्राह्मण जी, क्या आपके घर में मेहमान आते रहते हैं? हां, आते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया। बुद्ध ने पूछा,जब मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए क्या भोजन बनाते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया,हम एक बड़े भोज की तैयारी करते हैं। बुद्ध ने पूछा, अगर वे नहीं आते तो आप क्या करते हैं? ब्राह्मण बोला, हम भोज स्वयं खा लेते हैं। बुद्ध बोले,अच्छा, तुमने मुझे भोजन पर बुलाया पर तुमने मेरा स्वागत कठोर वचनों और आलोचना से किया। लगता है कि जो भोज तुम मुझे परोसने वाले थे, वह इसी का है। मैं तुम्हारे द्वारा परोसे भोजन को नहीं खाना चाहता। कृपया इसे वापस ले लो और स्वयं खाओ। बुद्ध ने महसूस किया कि जो भोज उन्हें दिया गया था, वह खाद्य पदार्थों का नहीं, बल्कि गालियों का था। उन्होंने वापस मुड़कर ब्राह्मण का तिरस्कार करने और उसे अपशब्द कहने के बजाय उसके प्रोध को स्वीकार नहीं किया। बल्कि वे उस स्थान से चले गए। इस प्रकार, प्रोध उसी के साथ रहा जो उसे प्रकट कर रहा था।।.....

A level of normalcy is ordinarily a prerequisite for conducting elections. At the same time, elections augment normalcy and add to its quality and endurance, by endowing it with legitimacy. Jammu and Kashmir has accrued this capital which should help it see through aberrations like Pahalgam in a social and political sense and help buttress security even while the state may have its hand in paused readiness. The terror attack was a first attempt to disrupt peace and distract attention, especially the youth from the democratic developmental path they so decisively chose in the two elections. The good thing is that the successful conduct of elections has fortified the state and the society of Kashmir against these and challenges, big or small, present or future. It is born out of the democratic churning of 2024 to keep growing; not to be doused by odds and ends or acts of insinuation and skepticism from within or without.

Hiding income or making wrong claims Your ITR could attract a 200% penalty

New Delhi. It's that time of the year again when taxpayers across the country start filing their Income Tax Returns (ITR). But hold on. If you're all set to hit submit, take a moment and double-check your return. Under the new ITR rules, even a small mistake or a false claim can lead to big trouble.

If a taxpayer hides actual income, a 200% penalty on the tax evaded is charged for misreporting. For underreporting, the penalty is 50% of the tax owed under Section 270A, as mentioned by ClearTax. Sounds serious? It is. That's why you need to be extra careful while filing your ITR, as even minor errors can result in significant financial consequences. Therefore, taxpayers must be vigilant and ensure all information is accurate to avoid hefty penalties.

COMMON MISTAKES IN ITR FILING

One of the primary areas of concern is the tendency of taxpayers to claim deductions under Section 80C without adequate proof or documentation.

Additionally, issues arise when taxpayers declare false House Rent Allowance (HRA) claims or list personal expenses as business expenses. Such practices can lead to severe penalties, regardless of the taxpayer's intentions or errors. Moreover, failing to report earnings from freelancing, crypto, or side jobs in your ITR may attract strict penalties. Make sure nothing is left out.

AVOIDING PENALTIES

To avoid incurring penalties, taxpayers should ensure that all claims are backed by legitimate documentation. Mistakes made by a Chartered Accountant (CA) or consultant do not exempt taxpayers from liability. The law holds the taxpayer accountable, not the person who prepared the return.

Therefore, it is imperative for individuals to review their tax returns meticulously before submission. This proactive approach can safeguard against potential errors and subsequent penalties.

Airtel says new fraud detection system shielded 3.5 million users in Delhi-NCR

NEW DELHI. Telecom operator Airtel on Thursday said its advanced fraud detection system has protected over 3.5 million users in Delhi-NCR within 43 days of launch of the new tool.

The statement assumes significance given the rising instances of digital frauds where unsuspecting users are lured online and deceived by scammers leveraging advanced techniques, malicious links and fake profiles. "As part of the nationwide rollout of its AI-powered fraud detection system, Airtel has successfully safeguarded more than 3.5 million users across the state, within just 43 days of launching its advanced fraud detection system," Airtel said in a release. The system, automatically enabled for all Airtel mobile and broadband customers, scans and filters links across SMS, WhatsApp, Telegram,



Facebook, Instagram, e-mail, and other browsers. "It leverages real-time threat intelligence to examine over 1 billion URLs daily and blocks access to harmful sites in under 100 milliseconds," the telco informed.

Gold prices keep falling after Israel-Iran ceasefire: Check the latest rates

Kolkata. Gold prices kept declining on Thursday, June 26 as the tension in West Asia seemed to ebb after the ceasefire between Israel and Iran was not violated for another day despite some rumblings to the contrary. According to market information, the price of the yellow metal fell by Rs 1,800 per 10 gms compared to the level at the beginning of the week. According to IBJA (India Bullion and Jewellers Association) data, the spot price of gold of the 999 variety fell below Rs 97,200 per 10 grams on Wednesday. It touched Rs 97,030 today June 26 in morning trade. According to data from the All India Sarafa Association, gold prices slipped Rs 300 to Rs 98,600 per 10 grams in New Delhi on Wednesday. Weak global trends prompted stockists to sell the metal, triggering the decline, said analysts. Gold 999 rates over the past few days in



India, gold prices have been falling since June 23 after the uneasy ceasefire agreement between Israel and Iran. According to IBJA (India Bullion and Jewellers Association) data, the price of 10 gms of gold 999 variety is as follows: The price of gold breached Rs 1 lakh per 10 gms for the first time on April 22 following the continuous uncertainty triggered by the retaliatory trade tariffs of US President Donald Trump. Analysts pointed out that though the prices have declined now, the markets will be on the lookout for any uptick in trade-related tensions and rising geopolitical risks in the coming weeks. It needs to be reiterated that Trump's tariffs have merely been suspended and not cancelled. Some analysts pointed out that gold could stay in the band of Rs 96,000 and Rs 98,500.

Indian banks still prefer funding fossil fuels project amid rising risk to investment: Report

An analysis shows that public banks provided roughly 75% of the coal loans while private banks financed roughly 83% of the total underwriting.

NEW DELHI. Even as India aggressively pushes for a clean energy transition, Indian banks have substantially financed fossil fuel and coal-fired power projects—totalling approximately USD 29 billion between 2016 and 2023—which could hinder and complicate the path to achieving net-zero emissions, states a recent report. Prepared

by Climate Risk Horizon, a Bangalore-based non-profit organisation that monitors climate-related risks for investors, the report highlights that the State Bank of India (SBI) and private lenders such as Axis Bank and ICICI Bank were among the top financiers of coal. Titled “Stuck in the Past: Coal Ties Hinder Indian Banks’ Energy Transition” the report indicates that India’s leading banks invested around USD 29 billion in coal during the specified period. Of this amount, approximately USD 15.2 billion was provided as coal loans, while USD 13.5 billion was allocated to coal underwriting services. Further segregating the data, the analysis shows that public banks provided roughly 75% of the coal loans while private banks financed roughly 83% of the total underwriting. According to the report, over these eight years, the amount of coal loans fluctuated significantly. Still, coal underwriting by Indian banks remained relatively stable with an average of USD 1.7 billion per year. Underwriting service is a process of mitigating risk for financial

transactions by financial institutions by guaranteeing repayment in case of damage or financial loss. Data shows that underwriting has become the dominant



channel for financing coal globally. “In India, higher indirect coal financing by private banks indicates a continued desire to profit from the climate-changing fuel, albeit with a lower risk exposure given the coal sector’s historical volatility,” said Anusha Das, co-author of the report. The report analysed that over 200 Financial Institutions worldwide—including more than 80 banks—have adopted coal

exclusion policies to align with decarbonisation and Net Zero goals. In India, Federal Bank, RBL Bank, and Suryoday Small Finance Bank have set an example by adopting coal exclusion policies. However, most banks have 25-35% of their loan books tied to coal, which raises serious concerns about their commitment to transitioning to clean energy and threatens investment. For instance, declining price of renewable energy compare to coal energy and stricter environmental scrutiny further stressed the debt of coal-power sector. According to the report, between 2016 and 2020, major Indian and foreign investors such as HDFC Mutual Funds and ICICI Prudential lost an estimated USD 3 billion in foregone earnings because of the underperformance of coal sector stocks. The data related to lending to coal-related projects was collected from open sources and Urgewald, a German non-profit advocating environmental and human rights organisation.

Housing sales drop 20% across top 7 cities in Q2 2025 as prices stay high

A sluggish Q2 masked early signs of recovery in India's housing market, with rising prices, cautious buyers, and skewed supply dampening sales—but softening rates and easing tensions may turn the tide.

New Delhi. Housing sales across India’s top seven cities declined 20% year-on-year in Q2 2025, with approximately 96,285 units sold compared to over 1.2 lakh units in the same period last year, according to the latest data from ANAROCK Research. On a quarterly basis, however, sales saw a modest 3% rise.

“The second quarter of 2025 was a rollercoaster for the Indian housing market,” said Anuj Puri, Chairman, ANAROCK Group. “The war-like climate pushed homebuyers into wait-and-watch mode, compounding the impact of soaring property prices over the past two years.” Puri attributed the soft Q2 sentiment to geopolitical tensions such as Operation Sindoor and the Iran-Israel conflict, along with continued price escalation across key markets. “Buyers paused, not disappeared,” he added. “Now, with domestic tensions easing and the RBI’s repo rate cut injecting fresh optimism, sentiment is already beginning to turn.”

CITY-LEVEL TRENDS Among the seven major cities, only Chennai

bucked the national trend, recording an 11% annual sales increase to around 5,660 units. The city also saw a sharp 40% rise from the previous quarter. In contrast, sales in MMR and Pune, which together contributed nearly half of all homes sold in Q2, fell by 25% and



27% year-on-year, respectively. Bengaluru saw sales rise slightly (1%) from the previous quarter but was still 8% below last year’s numbers. Hyderabad posted a 9% quarterly rise but dropped 27% annually. Kolkata saw the steepest sequential fall at 10%.

LAUNCHES AND PRICE TRENDS Developers launched 98,625 new units in Q2 2025, a 16% drop year-

on-year, as they responded to subdued demand. MMR led in fresh supply with over 28,000 units but saw a 36% annual decline. NCR was the only city with a supply uptick—launches rose 69% quarter-on-quarter and 10% year-on-year, driven heavily by high-end projects. “New supply continues to skew towards the upper end of the spectrum,” Puri said. Luxury and ultra-luxury homes (above Rs 1.5 crore) accounted for 46% of new launches, while the affordable segment (below Rs 40 lakh) made up just 12%. “This clear supply mismatch is pricing out large sections of the middle-income market.” Average residential prices in the top cities rose 11% year-on-year, with NCR leading the surge at 27%, followed by Bengaluru (12%) and Hyderabad (11%). However, quarterly price growth has begun to moderate, coming in at just 1%. “If prices remain in check and financing costs stay favourable, housing demand should bounce back in the second half of the year,” Puri noted.

Markets gain for third straight session as Indian benchmarks rise

CHENNAI. Indian equity benchmarks rose on Thursday, extending their two-day rally amid hopes of a ceasefire between Israel and Iran, despite weak cues from Asian markets. BSE Sensex, which rose 502 points in the early trade, settled at 83116.14, up 360.63 points or 0.44% at 12.03 noon. NSE Nifty climbed 131.60 points, reaching 25,376.35, marking a 0.57% gain for the session.

Both indices have risen nearly 1% over the previous two sessions, approaching nine-month highs. Key drivers behind the rally have been hopes of a ceasefire between Israel and Iran, which has calmed geopolitical risk—and lifted global sentiment. Weakening dollar and bond market softness bolstered metals and

commodity-linked stocks. June monthly F&O contracts expire tomorrow, adding volatility especially near 25,400–25,500 levels. Cumulative



foreign institutional investors (FIIs) selling of over Rs 9,500 crore in the past three sessions remains a headwind.

However, MSCI index was mixed, slipping 0.2% before firming modestly. Sector action in India

Metals outperformed (+1%) benefiting from weak dollar dynamics. Financials & large-caps like HDFC Bank (+0.7%) and Reliance (+1.3%) advanced.

Defense stocks also gained 1–2%, fueled by global defense spending positivity.

But, June derivative contract expiry is tomorrow—expect last-hour swings. Despite rally, foreign capital is still leaving—a drag on near-term momentum. Market experts expect the day to open positively, backed by the GIFT Nifty’s 40-point uptick and supportive global cues.

US Bitcoin Reserve signals a shift: An opening for India

India stands at a pivotal juncture. A measured Bitcoin strategy—perhaps a reserve pilot—could strengthen economic resilience and project modernity. As the US advances and nations like Bhutan adapt, India has a unique opportunity to lead.

New Delhi. The US Strategic Bitcoin Reserve, launched in January 2025 under President Donald Trump, has elevated digital assets to a global stage. Valued at more than \$20 billion as of June 2025, it underscores Bitcoin’s emerging role as a store of value. For India, this shift invites reflection: could Bitcoin, thoughtfully integrated, enhance our economic toolkit? The US initiative currently repurposes 200,000 seized Bitcoins as a buffer against inflation, a strategy cemented by last month’s White House Crypto Summit with clearly articulated plans to buy more Bitcoin by exploring budget-neutral manners. Thereby, expanding its Bitcoin reserve holdings in the coming times without hurting the taxpayer.

Three US states have now passed legislation authorising the deployment of public funds to purchase and hold Bitcoin

as a reserve asset, with more expected to follow. These measures reflect a growing recognition of Bitcoin’s potential to bolster fiscal resilience and serve as a hedge in uncertain economic conditions. This isn’t a reckless pivot, it’s a calculated step toward embracing digital assets’ legitimacy. For India, observing this offers a lens to assess whether Bitcoin could diversify our reserves, complementing traditional holdings in an uncertain global economy.

BHUTAN & BITCOIN: A REGIONAL PERSPECTIVE FOR INDIA

Bhutan provides a regional perspective. Since 2021, it has mined Bitcoin with hydropower, amassing a \$1 billion-plus reserve by May 2025. Born from tourism’s decline, this approach now supports public services and sustainability goals. India, with its renewable energy capacity, has the full scale of capability to adapt this model, though scale and regulation pose distinct challenges. Bhutan’s success suggests digital assets can stabilise economies, a point worth considering.

WHAT MAKES BITCOIN STAND OUT? Bitcoin stands apart as an asset without an issuer—a commodity, not a security, as the US SEC now recognises. Like gold, it has no central authority; no government, bank, or company controls it. This

decentralisation is its bedrock, setting the stage for three defining traits: scarcity, liquidity, and transparency. Only 21 million Bitcoins will ever exist, which, unlike traditional currencies or even assets like stocks, bonds, or commodities that face oversupply and hence inflation, has a fixed supply.



This mirrors gold’s finite nature but operates at digital speed. Bitcoin trades globally 24/7, offering liquidity unmatched by most decentralised assets; gold, by contrast, sits static in vaults or jewellery, less fluid in daily exchange. And its blockchain—a public, tamper-proof ledger—makes every single transaction verifiable to anyone, reducing the opacity that often clouds traditional markets. These qualities echo gold’s appeal: a trusted store of value beyond any single entity’s grasp. Yet Bitcoin transcends it, digital

and dynamic where gold is physical and inert. At \$100,000+ today, it’s this blend—gold’s scarcity with digital fluidity—that earns it the “digital gold” label by many including the White House. It’s an intuitive shorthand: finite and reliable like metal, but built for a borderless, tech-driven world. Bitcoin also stands out because of its programmability and portability. It can move at the speed of the internet, settle transactions with verification but, without intermediaries, and be stored securely with modern cryptography-based security.

In an increasingly digital and decentralised world, it aligns with how the next generations are thinking about money and value. THE ROLE OF REGULATION

Regulation remains pivotal. India’s crypto policy—taxed but unregulated—needs clarity to unlock potential. During its G20 presidency in 2023, India chaired the formation of a crypto working group with the IMF, tasked with shaping global standards. While its recommendations will take their due course, we are seeing other jurisdictions including Russia, China, and Brazil from the BRICS, and other G20 nations led by the US, race ahead—not pausing for consensus.



last five years, according to data from LSEG. Analysts say this shows that the company’s earnings have been rising fast enough to match the jump in share prices.

Nvidia, Microsoft, and Apple have been switching places frequently in the race to become the world’s most valuable company. Microsoft recently held the top position after overtaking Nvidia in early June. But now Nvidia is back at the top. Apple remains in third place with a market value of about \$3.01 trillion after a 0.63% rise in its stock price on Wednesday. Here’s a look at the top 10 most valuable companies in the world based on market capitalisation:

Mission Mathematics expanded to classes 6 to 10 in Delhi Government schools

The Directorate of Education (DoE) has directed Delhi Government schools to analyse Class 10 mid-term performance and identify learning gaps accordingl

Agency New Delhi. The Delhi Government's "Mission Mathematics and Special Enrichment Classes" initiative has now been extended to students of classes 6 to 10 for the 2025-26 academic session to strengthen maths learning and address learning gaps. The Directorate of Education (DoE) made the announcement in a departmental circular issued on Monday, citing improved performance in annual assessments and the Central Board of Secondary Education (CBSE) board examination results since the initiative began in 2022. Launched in response to poor mathematics performance in board exams, the programme initially focused on classes 8 to 10. It introduced activity-based worksheets, "Question of the Day" exercises, and assessment



tools to foster "joyful and concept-driven learning". These resources were expanded to Classes 6 to 10 in June 2024 and will now be shared digitally with schools for all targeted classes—three times a week—starting July 7. To further personalise support, DoE has directed schools to analyse Class 10 mid-term performance and identify learning gaps accordingly. A centralised tracking module is also being developed to monitor attendance and academic progress in Mathematics. **Eligibility and implementation** Students for the Special Mathematics Enrichment (SME) classes are selected based on their prior academic performance. For Classes 6, 9, and 10, students must

have scored at least 50 per cent with grace marks in Mathematics or passed via compartment exams. For Classes 7 and 8, students scoring 40 per cent or below in the previous year are eligible. In both cases, subject teachers may recommend additional students based on classroom performance. SME classes will be conducted in small groups of 20-25 students, before or after school hours. Schools have been allowed to appoint resource persons for these sessions, with dedicated funds already allocated, as per the circular. Teachers will have to maintain detailed records, including a separate notebook for each student. They have also been advised to use curriculum mapping to align Class 10 content with foundational gaps from previous years.

Accused should be given strictest punishment, says family of Delhi girl pushed off terrace

Agency New Delhi. "She was just a child... Her whole life was ahead of her," a teary-eyed Sonia said, as family members, neighbours and friends gathered around her. On Monday, Sonia's 19-year-old sister, Neha, was pushed off the terrace of the building she lived in with her family, allegedly by a 26-year-old man she knew. On Tuesday morning, the injured Neha succumbed to her injuries in Guru Teg Bahadur Hospital. "Multiple teams from Jyoti Nagar police station, Gokulpuri subdivision and Operations unit of North East were deployed to trace the accused, Taufeeq. He was arrested on Tuesday night from Rampur in Uttar Pradesh," DCP (North East) Ashish Mishra said. Neha's father Surendra works as a security guard, and she recently took up a job in a private firm. She studied till Class 12 and could not go to college because of the family's poor financial condition, police sources said. Anticipating communal tension, the police, meanwhile, have stepped up security in the area. Gaurav Gupta, Additional DCP (North East) said that Neha's family was contemplating getting her married soon. "Neha and the accused knew each other but she had not been speaking to him for some time. The accused found out that her family was planning to get her married. He was enraged," he said. A police officer said that he wore a burqa and called her to the terrace of the five-storey building. "They likely had an argument there after which he pushed her," said the officer. Taufeeq was no stranger to the family. "We have known him for three years... We considered him our brother. I don't know what happened in the last few months.

Four charred to death as Rohini building housing 3 plastic factories catches fire

Agency New Delhi. At least four persons died and three others sustained injuries after a building housing three plastic item manufacturing units caught fire at Rithala in Delhi's Rohini on Tuesday evening. The blaze was doused after a 15-hour operation on Wednesday. As per preliminary reports, the cause of the fire is suspected to be a short circuit. In a statement, the police said the owner of the building, Suresh Bansal, and his son Nitin Bansal, ran a factory on the ground and first floors. Nitin (31) is among the injured. Delhi Fire Service (DFS) officials, meanwhile, are also investigating the possibility of the fire being set off during a self-immolation bid by a factory worker. The deceased, all suspected to be migrant workers, are yet



to be identified, police said. An officer attached to DFS said they received a call regarding the fire at 7.30 pm on Tuesday. "A blaze had started at a four-storey building near Rithala Metro Station in Rohini Sector 5. At least 16 fire tenders were pressed into service," the officer said. Around 1.30 am on Wednesday, three charred bodies were recovered from inside the premises, the police said. Later, one more charred body was retrieved. "We will be conducting DNA tests if required. We are waiting for the family members of the victims to approach," a police officer said, adding that a case is being registered to probe the incident. An official in the mortuary of Dr Baba Saheb Ambedkar Hospital said, "No family members of the deceased have approached us so far." Besides Nitin, the other two injured have been identified as Virender (25) and Rakesh (30), who has sustained 80% burns.

'Told him to stay calm': robbers barge into businessman's farmhouse in Delhi's Ghitorni, take him to Gurgaon, loot Rs 30 lakh

Agency New Delhi. Four men, one of them claiming to be a delivery agent, allegedly barged into a businessman's farmhouse in Ghitorni in Delhi Monday night, robbed the premises, and took him in his car to his office in Gurgaon to take more cash. According to the Delhi Police, Karan Chopra, who has multiple CNG filling stations across Delhi and the National Capital Region (NCR), was at his farmhouse in Ghitorni with some of his family members when the incident happened. "A person came to the door, claiming to be a delivery boy. As soon as the complainant (Chopra) opened the door, three more men barged inside and took him hostage. They told him that they have guns. They told him to stay calm, and let them leave with the cash," a police officer said. The police officer said they then took Chopra to his office at M G Road in Gurgaon, and asked him to arrange for more cash. Chopra then directed his accountant at the office to comply with their demand. The robbers allegedly robbed him of Rs. 30 lakh in cash and some jewellery. After being released, Chopra called the police, and a case was filed. The suspects are yet to be traced. Amit Goel, Deputy Commissioner of Police (South West), said they received information about the robbery at the Vasant Kunj South Police Station. "On receipt of the information, SHO, along with staff, reached the spot, where they met complainant Karan Chopra. He alleged that three to four persons forcefully entered his house and office and looted around Rs 30 lakh. He told the police that he is engaged in the business of CNG gas distribution," he said. The police said crime and forensics teams were called to the spot immediately, and an investigation was launched.

Delhi man dupes travellers, airlines using forged death certificates; arrested

Akshay Sharma targeted international travellers, and his scam involved booking tickets, cancelling them, and then claiming refunds, the police said.

Agency New Delhi. A travel agency, a fake call centre, and forged death certificates: This is how a Delhi man allegedly duped hundreds of international travellers and airline companies by booking tickets, cancelling them, and pocketing the refunds, the Delhi Police said on Wednesday. Akshay Sharma, 40, a resident of Kirti Nagar and the director of AVS Holidays, was arrested on Tuesday by the Delhi Police Special Cell for allegedly orchestrating a sophisticated scam under the cover of a legitimate travel agency. According to the police, Sharma's alleged modus operandi involved getting crucial documentation from his customers, along with their financial details like credit card CVVs, on the pretext of booking their flight tickets. Once the tickets were booked, Sharma would use the documents to forge the death certificates of the



travellers and obtain a full refund from the airlines, the police said. His 'call centre employees' would then call the customers and tell them that their flights had been cancelled and give them a small fraction of the refunded

amount, the police added. Sharma was arrested on charges of cheating and forgery under sections 318(4), 319(2), 339/61(2) and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita and Section 66C of the Information

Technology Act. "During sustained custodial interrogation, the accused confessed to establishing and operating fraudulent call centres over several years, under the facade of a legitimate travel service provider. He admitted to orchestrating a scheme that primarily targeted US and other foreign nationals by posing as an authorised flight booking agency," Amit Kaushik, Deputy Commissioner of Police, Special Cell, said. "The illicit proceeds were partially returned to the victims—after deducting fictitious cancellation fees—or withheld entirely. Preliminary forensic analysis of seized electronic devices has revealed hundreds of forged documents used to facilitate these fraudulent claims," he added. The company has more than 500 employees, and multiple arrests will follow, a senior police official said.

Mother-in-law of Faridabad woman buried in pit arrested; police say victim was given juice laced with sleeping pills

Tannu Rajput's father-in-law, Bhoop Singh, has allegedly revealed that his family had conspired to murder her and reported her missing to mislead people.

Agency Faridabad. Five days after Tannu Rajput's decomposed body was found buried inside a pit outside her in-laws' house in Haryana's Faridabad, the police on Wednesday arrested her mother-in-law in the case. The Crime Branch (DLF) arrested Sonia, 45, after her husband, Bhoop Singh, who was arrested in the case earlier, allegedly confessed that the family had conspired to murder Rajput due to ongoing domestic disputes, including talks of divorce. The case was initially being probed as a dowry dispute.



According to the police, Singh allegedly revealed that he and his family had planned Rajput's murder. On April 21, Singh allegedly sent Sonia to her relatives in Uttar Pradesh to create an

alibi. The same day, a pit was dug outside their house, the police said. Rajput was allegedly given sugarcane juice laced with sleeping pills, and later that night, while she was unconscious, Singh strangled her with a dupatta, the police said. Her body was then buried in the pit with her husband Arun's assistance, the police said, adding that the family subsequently reported her missing to mislead people. While Arun is absconding, the role of Singh's daughter, Kajal, is under investigation.

'Nobody listens to us': Street vendors, rickshaw pullers protest at Delhi's Jantar Mantar against evictions

Street vendors in Delhi have alleged that they often face difficulties in retrieving their confiscated items from the authorities.

Agency New Delhi. Street vendors, rickshaw pullers and slum dwellers from across Delhi protested at Jantar Mantar Wednesday against evictions and demanded recognition and rehabilitation for urban workers. The protest was led by the Indian Hawkers Alliance, Mazdoor Awas Sangharsh Samiti and Delhi Rickshaw Chalak-Malik Sangharsh Association. Workers from various markets, such as Chandni Chowk, Sarojini Nagar, Meena Bazaar, GTB Nagar, India Gate, Kamla Nagar, Sangam Vihar, and Ratiya Marg, were present. Women dry fruit sellers from Jahangirpuri complained of theft when the authorities came to evict them. Rajini, a vendor who has sold dry fruits for the past eight years at Chandni Chowk, said, "We face loss of goods; sometimes we don't even get it back. They just make us run from one office to another saying that you don't

have the required documents. I sell perishable goods; they get spoiled if kept for long." A group of women street vendors from India Gate sat holding placards in the last row. "I have been doing this for the last ten years at the same location. Earlier, we never used to face any problems, but now officials and the police come and kick our goods, confiscate them and seek money. When we ask for our goods back, nobody listens to us," said Gulesha Khatoun. A few rows ahead sat Ritu Joshi, 40, a resident of Nehru Colony, Govindpuri, who feared whether her family would get accommodation if their camp is demolished. "Our camp is also about to get demolished, they promised us to give flats, but I fear if they will, what if we are stuck



like some families of the Bhoimiheen camp who still don't have places to live," she said. Sanjeev Kumar, 34, a rickshaw puller from Karampura, said that for the last two or three years, the traffic police have been confiscating his rickshaws. "I have lost two rickshaws in the last few years. They

said that we have sent it to Hapur, go get it from there. How will I be able to go?" he asked. Sandeep Verma, the convener of the Indian Hawkers Alliance and a member of the town vending committee (TVC) for the Sadar Paharganj Zone within the Municipal Corporation of Delhi (MCD), expressed his dissatisfaction with the way the authorities treat street vendors in the area. "There are many flaws in the previous survey conducted; officials don't even consult the elected TVC for any actions or decisions. The vendors are ready to pay fees for the space, but first, the authorities need to recognise us as we have been historically living and selling things over here," Verma said.

NEWS BOX

12 killed in attack on celebration in Mexico's Guanajuato state city

MEXICO CITY. Twelve people were killed overnight in the Mexican state of Guanajuato when gunmen opened fire on a celebration in the city of Irapuato, authorities said Wednesday. People were dancing and drinking in the street in celebration of St. John the Baptist when the shooting began. Revelers screamed and ran to escape the gunfire, according to videos circulated online. Irapuato official Rodolfo Gómez Cervantes, said in a news conference Wednesday that the number of victims had risen to 12. Some 20 others were wounded. President Claudia Sheinbaum lamented the attack, saying that it was under investigation.

Last month, seven people were killed in a shooting that targeted a party organized by the Catholic Church in San Bartolo de Berrios, Guanajuato. Guanajuato, which is northwest of Mexico City, has been one of the country's most violent states, as various organized crime groups battle for control. There have been 1,435 homicides in the state through the first five months of the year, more than double any other state.

Israel kills at least 60 Palestinians waiting for aid at distribution sites of US-backed GHF, in last 24 hrs

world. Israel has killed at least 60 starving Palestinians who were waiting for the much-needed humanitarian aid at the distribution sites of the US-backed and Israeli military-established Gaza Humanitarian Foundation (GHF) in the last 24 hours, reported Al Jazeera.

The latest in a string of deadly attacks on desperate aid seekers came after the United Nations had condemned Israel's "weaponisation of food" against the Palestinians after a three-month-long blockade of humanitarian assistance, which was partially lifted only to replace the established aid distribution systems with the GHF. Rights groups and the UN had refused to cooperate with the GHF, slamming it as a "death trap" for Palestinians and accusing it of aiding Israel in its genocidal war in Gaza.

The UN agency for Palestinian refugees, UNRWA, called the GHF an "abomination" that has put Palestinians' lives at risk, while a spokesman for the UN human rights office, Thameen Al-Kheetan, condemned the "weaponisation of food" in the territory. According to Gaza's health ministry, Israel has killed more than 500 Palestinians at aid distribution sites since the GHF began operations last month. Meanwhile, Israeli forces also shot dead a 13-



year-old Palestinian boy during a raid on al-Yamoun, west of Jenin in the occupied West Bank on Wednesday. The boy, Rayan Tamer Housheh, was shot in the neck. Israel's genocidal war on Gaza has so far killed at least 56,077 Palestinians, mostly women and children. Israel has also targeted and killed hundreds of journalists, health care workers and aid workers.

Haka and flag-burning: Why New Zealand is seeing anti-immigration protests

world. "Faith, flag, family," chanted the crowd in Central Auckland as anti-immigration protestors gathered under the leadership of Destiny Church's Brian Tamaki. The demonstrators, many of whom performed the haka, tore, stomped on, and burned flags representing Hinduism, Islam, Buddhism, and Palestine, each act of destruction followed by traditional war dances. The protest reflected a growing unease among some segments of New Zealand's population regarding the country's changing immigration landscape.

Tamaki, a radical religious leader known for courting controversy, made his intent clear. "The spread of non-Christian religions is now out of control," he said, adding that "Any type of immigration without assimilation is invasion." The response from the country's leaders was swift and firm. Acting Prime Minister David Seymour called Tamaki's views "un-Kiwi". He also asserted that "New Zealand's great strength is that we are a nation of pioneers who moved here to give their children a better tomorrow."

New Zealand's Police Minister Mark Mitchell also condemned the protest, describing the event and its use of sacred cultural practices as "vile rhetoric and behaviour," which, he said, had no place in the country. But New Zealand has seen a larger anti-immigration sentiment. Here's why.

WHY AN IMMIGRATION PROBLEM IN NEW ZEALAND?

The outburst in Auckland did not emerge in a vacuum. New Zealand, a country of just over 5.3 million people, has seen a dramatic surge in migration since late 2022. While the government has emphasised the need for skilled immigrants, particularly in areas like education, it has also sought to prioritise native citizens for jobs where there are no shortages. The government is focused on attracting and retaining highly skilled migrants such as secondary teachers, where there is a skill shortage," said Immigration Minister Erica Stanford.

Bezos and Sanchez arrive in Venice as protesters say their wedding highlights wealth inequality

Their wedding has drawn protests by groups who view it as a sign of the growing disparity, with locals saying it highlights how their needs are ignored amid mass tourism.

VENICE. Amazon founder Jeff Bezos and Lauren Sanchez arrived in Venice, Italy, on Wednesday ahead of their star-studded weekend wedding, which has galvanized an assortment of protesters. Bezos waved from a water taxi as he and Sanchez arrived at the dock of the Aman Hotel on the Grand Canal with two security boats in tow. Their wedding has drawn protests by groups who view it as a sign of the growing disparity between the haves and have-nots, while residents complain it exemplifies the way their needs are disregarded in the era of mass tourism to the historic lagoon city.

About a dozen Venetian organizations — including housing advocates, anti-cruise ship campaigners and university groups — have united to protest the multi-day event under the banner "No Space for Bezos," a play on words also referring to the bride's recent space flight. They have staged small-scale protests, unfurling anti-Bezos banners on iconic Venetian sites. They were joined Monday by Greenpeace and the British group "Everyone Hates Elon," which has smashed Teslas to protest Elon Musk, to unfurl a giant banner in St. Mark's Square protesting purported tax breaks for billionaires. On Wednesday, other activists launched a float down the Grand Canal featuring a mannequin of Bezos clinging onto an Amazon box, his fists full of fake dollars. The British publicity firm that announced the stunt said it wasn't a protest of the wedding "but against unchecked wealth, media control, and the growing privatisation of public spaces." The local activists had planned a more organized protest for Saturday, aiming to obstruct access to canals with boats to prevent guests from reaching a wedding venue.

They modified the protest to a march from the train station after claiming a victory,



asserting that their pressure forced organizers to change the venue to the Arsenale, a more easily secured site beyond Venice's congested center. It will be a strong, decisive protest, but peaceful," said Federica Toninello, an activist with the Social Housing Assembly network. "We want it to be like a party, with music, to make clear what we want our Venice to look like." Among the 200 guests confirmed to

be attending the wedding are Mick Jagger, Ivanka Trump, Oprah Winfrey, Katy Perry and Leonardo DiCaprio.

Venice, renowned for its romantic canal vistas, hosts hundreds of weddings each year, not infrequently those of the rich and famous. Previous celebrity weddings, like that of George Clooney to human rights lawyer Amal Alamuddin in 2014, were embraced by the public. Hundreds turned out to wish the couple well at City Hall.

Bezos has a different political and business profile, said Tommaso Cacciari, a prominent figure in the movement that successfully pushed for a ban on cruise ships over 25,000 tons traveling through the Giudecca Canal in central Venice. "Bezos is not a Hollywood actor," Cacciari said. "He is an ultra-billionaire who sat next to Donald Trump during the inauguration, who contributed to his reelection and is contributing in a direct and heavy way to this new global obscurantism."

Analysis: A battered Iran faces an uncertain future after its grinding war with Israel

DUBAI. The bombing has quieted in Iran's 12-day conflict with Israel. Now its battered theocracy and 86-year-old Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei must regroup and rebuild in a changed landscape. Israeli airstrikes decimated the upper ranks of Iran's powerful Revolutionary Guard and depleted its arsenal of ballistic missiles. Israeli missiles and American bunker buster bombs damaged the nuclear program — though how much remains disputed. Khamenei went into deep isolation in an undisclosed location, appearing only twice in videos as the Israelis had free rein over the country's skies. Iran's self-described "Axis of Resistance," a group of allied countries and militias in the Mideast, has been mauled by the Israelis since Hamas' Oct. 7, 2023, attack. Foreign

support Tehran may have expected from China and Russia never



materialized. At home, old problems remain, particularly an economy wrecked by international sanctions, corruption and mismanagement. "Iran's leadership has been dealt a heavy blow and will be conscious of preserving the ceasefire, which gives the regime breathing room and allows

space to focus on internal security and reconstruction," the Eurasia Group said in an analysis Wednesday. Shoring up loyalty One thing Israel's campaign showed was how much its intelligence agencies have infiltrated Iran, particularly its swift pinpointing of military and Guard commanders and top nuclear scientists for strikes. The No. 1 task for Khamenei may be to root out any suspected disloyalty in the ranks. There must be some sort of purge. But who will implement it? That is the question," said Hamidreza Azizi, a visiting fellow at the German Institute for International and Security Affairs. "This level of distrust that apparently exists now is going to paralyze any effective planning or security overhaul," he said.

Trump grapples for upper hand in debate over damage caused by US strikes on Iran

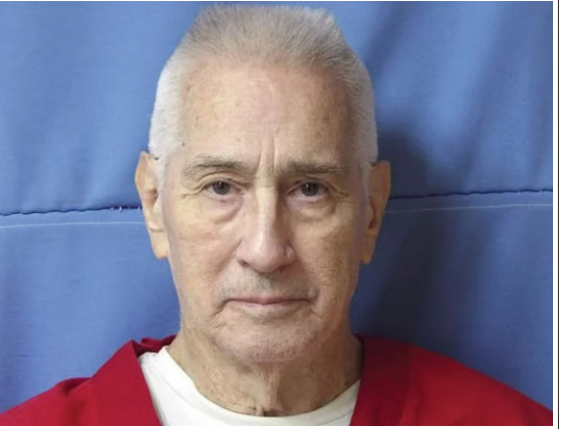
THE HAGUE. President Donald Trump on Wednesday rejected an early intelligence assessment that U.S. strikes inflicted only a marginal setback on Iran's nuclear program, insisting that his country's spies did not have the full picture and defending his own swift conclusion that American bombs and missiles delivered a crushing blow. "This was a devastating attack, and it knocked them for a loop," Trump said as his administration scrambled to support his claims, made only hours after the attack, that Iranian nuclear facilities were "completely and fully obliterated." Trump said Defense Secretary Pete Hegseth and other military officials would hold an "interesting and irrefutable" news conference Thursday morning to "fight for the Dignity of our Great American Pilots" who carried out the mission. He wrote on social media that "these Patriots were very upset" by "Fake News" reports about the limited impact of the strikes. The issue dominated Trump's attendance at NATO's annual summit in the

Netherlands, which was otherwise focused on European security. The White House highlighted an Israeli statement that Iran's nuclear efforts were delayed by years, much longer than the few months determined by American intelligence. A spokesperson for the Iranian foreign ministry also said the facilities have suffered significant damage. But those comments fell short of Trump's hyperbole and did little to suggest that U.S. strikes had eliminated the threat of Iran developing a nuclear weapon. Secretary of State Marco Rubio, speaking in an interview with Politico, limited his own assessment to saying Iran was "much further away from a nuclear weapon today than they were before the president took this bold action." Drawing reliable conclusions about the impact of the U.S. strikes remains difficult, especially only days after they took place. That makes the issue a breeding ground for competing claims that could determine how American voters view Trump's risky decision to join Israel's attacks on Iran.

Jeffrey Lewis, a professor of nonproliferation at the Middlebury Institute, said Trump was trying to have it both ways. "If it's too early to know, why is Trump saying it's obliterated?" he said. "Either it's too early to know, or you know." What's next? Also at stake are Trump's next steps in the Middle East, where diplomatic efforts could be required to prevent Iran from rebuilding its nuclear program. Trump said U.S. and Iranian officials would meet soon, resuming a dialogue that was interrupted by nearly two weeks of war, even as he suggested that negotiations were no longer necessary. "I don't care if I have an agreement or not," Trump said, because Iran was too badly damaged to even consider rebuilding its program. "They're not going to be doing it anyway. They've had it." Iran maintains that its atomic ambitions are for peaceful purposes, while U.S. and Israeli leaders have described the country's nuclear program as the precursor to obtaining a nuclear weapon.

Mississippi executes the longest-serving man on the state's death row for 1976 killing

PARCHMAN. The longest-serving man on Mississippi's death row was executed Wednesday, nearly five decades after he kidnapped and killed a bank loan officer's wife in a violent ransom scheme. Richard Gerald Jordan, a 79-year-old Vietnam veteran with post-traumatic stress disorder whose final appeals were denied without comment by the U.S. Supreme Court, was sentenced to death in 1976 for killing and kidnapping Edwina Marter. He died by lethal injection at the Mississippi State Penitentiary in Parchman. The execution began at 6 p.m., according to prison officials. Jordan lay on the gurney with his mouth slightly ajar and took several deep breaths before becoming still. The time of death was given as 6:16 p.m. Jordan was one of several on the state's death row who sued the state over its three-drug execution protocol, claiming it is inhumane. When given an opportunity to make a final statement Wednesday, he said, "First I would like to thank everyone for a humane way of doing this. I want to



apologize to the victim's family." He also thanked his lawyers and his wife and asked for forgiveness. His last words were: "I will see you on the other side, all of you." Jordan's wife, Marsha Jordan, witnessed the execution, along with his lawyer Krissy Nobile and a spiritual adviser, the Rev. Tim Murphy. His wife and lawyer dabbed their eyes several times. During a news conference after the execution, Keith Degruy, a spokesperson for Marter's family, read a statement on behalf of her two sons and husband, who were not present at the execution. "Nothing will bring back our mom, sister and our friend. Nothing can ever change what Jordan took from us 49 years ago. Jordan tried desperately to change his ruling so he can simply die in prison. We never had an option," he said. Jordan's execution was the third in the state in the last 10 years; previously the most recent one was carried out in December 2022. It came a day after a man was put to death in Florida, in what is shaping up to be a year with the most executions since 2015.

Youth-led protests erupt again in Kenya over police brutality and poor governance

NAIROBI. Youth-led protests against police brutality and poor governance have erupted across Kenya again on Wednesday, with thousands making their way to the central business district in the capital, Nairobi. The protests, which coincided with the first anniversary of demonstrations opposing tax hikes that left 60 people dead and 20 others missing, followed last week's rallies that demanded answers for the unexplained death of a Kenyan blogger while in police custody. Frustration is growing, especially among Generation Z, over police violence, economic struggles, and government mismanagement. The Communications Authority of Kenya has directed local media to stop all live broadcasts of the protests halfway through the day as President William Ruto warned that violence wouldn't be tolerated.

Many turned to social media to share updates and remember slain protesters. Others posted anti-government messages and memes. On the streets, some could be seen

offering protesters water.

Here's why unrest is gripping Kenya: Police brutality

Calls for accountability have grown louder in Kenya after a street hawker was killed during last week's protests. A Kenyan court has given detectives 15 days to complete investigations into two police officers suspected of the shooting. This came as young people flooded social media platforms throughout the week with commemorations of protesters killed last year. At the time, Ruto apologized and vowed to end police brutality as the top police chief resigned. "Not a single officer has been held to account," said Hussein Khaled, a human rights activist, adding that people took to the streets "to demand justice in terms of compensation ... arrest of those officers who were involved ... police reforms because too many Kenyans are losing their

lives" to police brutality. Economic frustration

Last year's deadly protests strongly opposed a finance bill that raised taxes significantly to address debt, putting an undue burden on



young, educated people struggling with unemployment and a rising cost of living. Ruto later scrapped the bill. Some tax proposals were reintroduced later, drawing

widespread criticism and calls for Ruto's resignation, following the appointment of a new but widely criticized cabinet. A revamped healthcare levy also changed standard premiums to a progressive tax, based on income. United Nations' data shows that 70% of sub-Saharan Africa is under the age of 30, with 67% of Kenya's young people unemployed.

Both the health and the education sectors, which greatly affect the youth, are seemingly sinking due to misguided policies and failure to provide needed resources. At the same time, there appears to be unlimited funds for 'aristocratic' luxuries," said Macharia Munene, professor of History and International Relations at United

States International University Africa in Nairobi, referring to some state people's spending that has been strongly condemned.

NEWS BOX

After Shamar Joseph runs through Australia, Ian Healy responds to sledge at pacer

NEW DELHI. Former Australia wicketkeeper Ian Healy has responded to his sledge against Shamar Joseph after it went wrong on Day 1 of the first Test. Healy had taken offense to the comments made by Shamar to recalled Aussie opener Sam Konstas and felt that the West Indies pacer was picking on the 19-year-old. The former wicketkeeper said that Shamar had been sub-par after his Gabba performance, where he rocked the Aussies with a seven-wicket haul and guided West Indies to a famous win. Healy ended his comment by saying that Shamar was no Curtly Ambrose. He's had a terrible year since he went through us at the Gabba," Healy said on SENQ Breakfast. "Shamar has come out today and



said 'just look out and watch what is coming'. OK Shamar, well, you've delivered crap all year." "He'd better improve, that's what I'm saying in the dressing room. He's got real trouble. You're not Curtly Ambrose champ." However, Healy was left with egg on his face as Shamar picked up four wickets, including Konstas to bundle Australia out for 180. 'Sort of talked about what the dressing room might say' Healy commented on his comments on Shamar and said they were taken out of context and labelled as sledging. The former wicketkeeper said that he was saying what the Australian dressing room might say about Shamar. Healy did end his response with a cheeky dig on Shamar and the jewellery he was wearing. "Yesterday, when I talked about backing up Sam Konstas when an opponent sledges him I sort of talked about what the dressing room might say – is that the context, do you reckon, that I was talking about?" Healy asked co-host, NRL great Corey Parker. "Do you believe I was talking about what the dressing room might say to Konstas, or was it me saying something against Shamar Joseph?" "Geez, they've come out at me, haven't they! They've said 'oh no, I've sledged Shamar!' Apparently, it's saying I've had a personal dig at Shamar."

ENG vs IND: How Ben Duckett and Ollie Pope neutralised Jasprit Bumrah in 1st Test

New Delhi. I've faced him in a five-Test series before. I know what he's going to do to me, and the good thing about that is I know what skills he has," Ben Duckett said before the start of the 5-match Test series against India. For someone with Ben Duckett's history of interviews, it was a brave statement to make, given a backlash was expected if he were to fail against the best bowler in the world. But here we are, a full five days of Test cricket later, with Ben Duckett smiling ear to ear after he helped England gun down a 371-run total in Leeds. Ben Duckett's breakdown of Bumrah was methodical, something that we have rarely seen by an opening batter in a Test match. It was very Travis Head-esque in many ways. He knew that if he was able to survive the first spell, runs would be there for the taking. While we harp on Duckett, who is



slowly getting into the conversation of one of the best all-format batters going around, one more name needs to be mentioned. Ollie Pope, the England vice-captain, came into the Test series with his spot in question. At the pre-match press conference, Ben Stokes had to explicitly mention that Pope would be playing ahead of Jacob Bethell in the first game of the series. And that trust was paid in full. Like he does in most series, Pope started exceptionally well. His century in the first innings, where he batted from the second over itself, was instrumental in England nullifying India's massive first innings total of 471 runs. Pope, who has been dismissed by Bumrah five times in the nine Test matches, put up a brave face and executed a plan that might get replicated in the near future against the star India fast bowler. Pope rotated strike often against Bumrah, handling the bowler with Ben Duckett. The constant changes of strike did not let Bumrah settle. He had to keep switching his plans between Duckett and Pope, which did not allow him to settle into a rhythm. This came in sharp contrast to Bumrah's bowling against Zak Crawley, whom Bumrah was able to overhaul by bowling six straight balls in the first over of the England innings.

AUS vs IND: Tickets for Sydney ODI and Canberra T20I sold out in just two weeks

Cricket Australia has announced that tickets for two matches in India's white-ball tour this November were snapped up within just two weeks of going on sale.

NEW DELHI. Tickets for two matches in the upcoming white-ball series between Australia and India, scheduled for November this year, have sold out within two weeks of going on sale. According to Cricket Australia, over 16 percent of the tickets sold were purchased by Indian fan clubs, with some setting records for the most tickets bought by a single buyer for a single match. "Exhausting our public ticket allocation for the SCG ODI and Manuka Oval T20I four months before the series is a testament to the tremendous interest in the upcoming season amongst cricket fans," Koel Morrison, Executive General Manager Events & Operations, Cricket Australia, said. The last time the two sides met in Australia, the hosts ended up winning the ODI series 2-1 while India took the T20I series 2-1 as well.



INDIAN CRICKET AUSTRALIA 'S GOLDEN GOOSE' Cricket Australia's CEO, Todd Greenberg, has highlighted how Indian cricket's involvement has played a major role in overturning their debt owed to the Commonwealth Bank. The association had taken a loan of 300 million Australian dollars during the COVID-19 pandemic period.

When India toured in 2021, the series reduced their deficit by generating a revenue of 31.9 million Australian dollars. In addition, the series in 2024-25 also helped Australia reduce their deficits. Earlier this month, CA's new CEO, Todd Greenberg, had talked about the importance of Indian games for the cricket board. During the Covid pandemic in

2020, it was reported that Cricket Australia had to take a loan of A\$300 million from the Commonwealth Bank. "The Indian series in 2021 helped the Australian board. And in October last year, they announced a deficit of A\$31.9 million (\$21.34m). The last 2024-25 series against India in Australia further boosted the finances of the CA," Greenberg said. "I agree we've still got a lot of work to do, and we would like to be attracting more of those communities to be playing cricket, but part of that challenge is on us in how we offer participation. I think our participation offerings in this country are very traditional, and they have historically been offered in the same way to the same types of people over generations. And if we're going to attract a new generation of participants, then we need to do things differently. We need to think differently. We need to communicate differently, and we need to make sure that the clubs and our environments are both safe and welcoming and inclusive," Greenberg mentioned. The CEO reiterated that they have a long way to go, and one of his biggest goals is to fully integrate the sport within the diverse communities within the country.

England Cricket Board and BCCI join hands to scuttle ambitious Saudi T20: Report

- ➡ Saudi T20 league is a USD 400 million project backed by Saudi investors
- ➡ IPL and The Hundred franchises generate billions in revenue
- ➡ Cricket Australia keen on partnering with Saudi investors



Test Championship final at Lord's this month, the ECB and BCCI agreed to unite in opposing the new league. The boards agreed they would not issue "no objection certificates" to their players to sign up for the new competition, as well as lobbying the International Cricket Council (ICC) to withhold their endorsement," the newspaper wrote. Apparently Cricket Australia (CA) was keen on partnering with Saudi investors in the league. "Under plans that emerged in Australia this year, Saudi's SRJ Sports Investments has pledged to inject USD

400m to set up the new league, which would have eight teams playing four tournaments in different locations each year in a set-up that has been compared to tennis's Grand Slams," Guardian said. For CA, the main aim is to earn profit from the cash inflow by a private investor as the Big Bash League (BBL) franchises are owned by the governing body and the states. However, IPL is a USD 12 billion product and the ECB is all set to get richer by GBP 520m (USD 700 million) from the sale of 49% of the eight 'Hundred franchises'. "Cricket South Africa raised more than GBP 100m (USD 136 million) by selling franchises in its SA20 competition to Indian Premier League owners three years ago." The paper also reported that the ICC, currently run by former BCCI secretary Jay Shah, is unlikely to go against the wishes of the Indian board.

Why was Jasprit Bumrah's participation not kept a secret Aakash Chopra questions call

New Delhi. Aakash Chopra has questioned why Jasprit Bumrah's participation in the England series wasn't kept a secret. Bumrah's workload management was a big question heading into the series and India coach Gautam Gambhir said at the press conference before the series that the pacer spearhead would only play 3 Tests. Gambhir reiterated this while talking to reporters after the loss at Headingley and said that their plan with Bumrah would remain the same. Chopra, speaking on his YouTube channel, wondered if it was really necessary to publicise this, and he suggested that India should have made England play the guessing game. "Bumrah said he will play three matches only, and I am thinking whether it was required to publicize it. Why was it not kept a secret? We don't announce our team as well. So why was it necessary to reiterate it repeatedly before the start of the tour that he would play three matches only? Let them guess. You play whichever Tests you wish," said Chopra. Chopra feels that if Bumrah will play the second Test at Edgbaston, then it means he will be part of only one of the

three remaining matches. This will allow England to prepare pitches accordingly for the rest of the series. "You have played one, and you know you can play only two of the remaining four matches, which is not a good



thing. If you play the second as well, you will play one of three. So, suddenly, the opposition gets into a great frame of mind that Bumrah, your biggest strength, is also not there. You can prepare pitches accordingly," said Chopra.

'Next generation of Indian fast bowlers will have to be prepared' Chopra feels that a new generation of Indian fast bowlers will have to be prepared as there are doubts about Bumrah's availability, Mohammed Shami is reaching the end of his career and Mohammed Siraj isn't hitting the levels that were expected from him. "The next generation of Indian fast bowlers will have to be prepared. It's a serious issue. There were two important pillars of India's good performances away from home. One was batters starting to score runs, but it doesn't work out with that as you need to pick up 20 wickets. So Mohammad Shami and Mohammed Siraj were outstanding with Jasprit Bumrah," said Chopra. I also remember Ishant Sharma, and Bhuvneshwar Kumar's Lord's Test. When there are doubts about Bumrah's availability, who will take the responsibility going forward, because Mohammad Shami, I think that story is not over, but it is close to an ending. Mohammed Siraj is good, but he hasn't reached the rank of Bumrah or Shami."



and the players wanted to give a 'gift' to Australia. Rohit said that the players knew if they beat Australia, then Aussies would be knocked out of the tournament. "Australia had ruined our and the whole country's November 19 in ODI WC Final, so we should also give them a gift. These kinds of things were talked about in the dressing room. We had it in our minds that if we win this match, Australia will be out of this T20 World Cup," said Rohit in the interview with Star Sports. The win against Australia acted as the catalyst to India's momentum as they went all the way and claimed the T20 World Cup 2024 title by beating South Africa in the final.

Who could join Carlos Alcaraz, Jannik Sinner in new Big Three John McEnroe reveals

➡ American tennis legend John McEnroe has called for the emergence of a third standout player to join Carlos Alcaraz and Jannik Sinner in forming a new Big Three. He believes that a strong third contender would raise the level of competition and named three rising stars as potential candidates.

New Delhi. The American tennis great, John McEnroe, highlighted how the sport was in need of one more star to rival the towering modern-day stars in Carlos Alcaraz and Jannik Sinner to form the next generation's

'Big-Three'. The term is a fairly common usage to denote the trio of Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic, who ruled the sport for about two decades. With Federer and Nadal having retired and Djokovic already going on a downward spiral in terms of his form, the sport has seen Alcaraz and Sinner emerge as the two best players in the men's singles division. Alcaraz has already begun dominating, with two consecutive Wimbledon and French Open titles and a lone US Open crown in 2022. Similarly, Sinner is also making his mark, with the Australian Open and US Open titles to his name. With Wimbledon set to begin on June 30, later this month, both men will be considered favourites to take home the men's singles title. But the question remains: does anyone have what it takes to rival these two on the court? "It's going to be an interesting time to see if there's another player or two who can break in with those two the way



Novak (Djokovic) did when he was trying to get to the same level as Roger (Federer) and Rafa (Nadal)," McEnroe was quoted as saying by Reuters. The recent French Open final was a testament to how hard-fought the rivalry between the two top stars is. Despite being two sets down, Alcaraz saved three match points and staged a stunning comeback to win the contest, which turned out to be the longest final in French Open history. "It shows you what type of player he was that he was able to do that. But right now,

there's a void," he added. WHO CAN RIVAL ALCARAZ-SINNER DOMINANCE? When it comes to who can rival these two, McEnroe mentioned some of the younger stars in Jakub Mensik (19), Joo Fonseca (18), and Ben Shelton (22) as his picks. "One of those two guys or Ben would be my choice right now," McEnroe said. "I think it would be important to get another guy or two to add to the mix. That would be really helpful," he added. Shelton is probably amongst the well-known faces, considering he is placed at 10th in the ATP rankings. His most notable feat was making it to the Australian Open semi-final in 2025. Mensik is still making his way up to the top tiers, but he has already had one win over Djokovic in the Miami Open earlier this year, in straight sets. It's not every day that the Serbian legend gets taken down like this, and it could be a precursor for what to expect later on in his career.



Janhvi Kapoor

Sweats It Out In Gym, Shares Glimpse Of Rigorous Workout Session

Janhvi Kapoor is a fitness lover and continues to inspire fitness enthusiasts with her dedication to staying fit. The Mr. & Mrs. Mahi star took to social media to give fans a peek into her rigorous workout routine, and it's safe to say — she's not cutting any corners when it comes to training hard. Taking to her Instagram stories, Janhvi shared a photo in which she is doing Pilates. Her trainer Namrata Purohit shared the same photo. Recently, the actress made debut at Cannes red carpet. Her look went viral on social media. Her boyfriend Shikhar Pahariya and sister Khushi also joined her.

Recently, Janhvi Kapoor and Shikhar Pahariya's London getaway has taken over the internet, especially after a heart-melting moment between the rumoured couple went viral. In a video that has now caught fans' attention, Janhvi is seen casually eating from Shikhar's plate, even though the same dish is served to her. Shikhar looks at her affectionately, and Janhvi returns the gaze with a sweet, cheeky smile.

The video was part of a series of photos and clips Janhvi recently shared on her Instagram, giving followers a peek into her vacation. She was seen posing confidently in a black tank top and green cargo trousers in front of a scenic London bridge. Other photos included wholesome sister moments with Khushi Kapoor, with whom she enjoyed a picturesque picnic by the lakeside and even went horse riding. The adorable moment with Shikhar in the final slide of her post has especially captured fans' attention.

Janhvi had previously spoken about her relationship with Shikhar Pahariya on Koffee With Karan 8. Host Karan Johar teased her about their on-again, off-again dynamic, to which Janhvi responded, "Have you heard that song, Nadaan Parindey Ghar Aaja? Shikhar used to sing that to me a lot." The actress had also been spotted wearing a necklace bearing his name in the past. Earlier this year, Shikhar accompanied Janhvi to the Cannes Film Festival, where she attended the premiere of her upcoming film Homebound. Directed by Neeraj Ghaywan, the film also stars Ishaan Khatter and Vishal Jethwa. On the work front, Janhvi has a packed schedule. She will be seen in Param Sundari opposite Sidharth Malhotra, Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari alongside Varun Dhawan, and Peddi with Ram Charan.



Sonam Kapoor And Isha Ambani Bring Star Power To Serpentine Summer Party, Pose With Cate Blanchett



Bollywood star and global fashion icon Sonam Kapoor yesterday visited the Serpentine Gallery and was also announced as Member of the Summer Party Host Committee while attending Arpita Singh's exhibition: Remembering. Following the exhibition, Sonam attended the Serpentine Summer Party, co-hosted by Academy Award Winner Cate Blanchett which is an invitation-only fundraiser designed to bring together leading individuals and supporters of the institution from the worlds of art, fashion, business and technology.

Sonam Kapoor was seen posing with none other than two-time Oscar-winning actress Cate Blanchett. Cate, who is regarded as one of the most accomplished and revered figures in Hollywood, has won Academy Awards for her performances in The Aviator and Blue Jasmine. At the event, she made a bold sartorial statement in an intricately embellished dress featuring seashells, metal accents, and a sculptural hip detail — a look that was nothing short of avant-garde and theatrical, in true Blanchett fashion.

Also in attendance was Isha Ambani, who looked radiant as always in a champagne-toned beaded dress that shimmered in the evening light. The sleeveless dress featured a petal-like pattern, delicate embellishments, and a soft flared hem that added to the dreamy vibe. Isha's soft waves, natural makeup, and sparkling heels completed the look — she truly looked elegant and effortlessly beautiful.

At the Summer Party, Sonam, the global ambassador for the French luxury fashion house Dior, sported a Kimono jacket from the Dior Fall 2025 collection, embracing cultures through the world with her fashion. Others present at the fundraiser included Isha Ambani, Eiza González, Alicia Vikander, Rebel Wilson, Georgia May Jagger, Lady Amelia Spencer, Lady Eliza Spencer, Lily Allen and more.

Esha Gupta Reacts To Being Called A 'Sex Symbol': 'It's Not A Good Title To Have'



Actress and model Esha Gupta has shared her thoughts on being called a "sex symbol" in the industry. The tag, often associated with actresses, is something that she dealt with as people stereotyped her based on her striking features. Speaking to Siddharth Kannan on his YouTube show, Esha expressed her frustration at being associated with "sex." The conversation around this began when the host enquired about the people who tried to pull her down in the industry. She candidly revealed that the agency she was eyeing for a debut with refused to do so because a "director-producer" asked them not to, as they were planning to launch another big artist. The same people also made her feel bad about her looks.

"In the beginning, I did not stereotype myself; people did it. And I don't think it was the media either, the media does not do that. You are feeding the media; it is the people who feed the media," she said. Esha further reflected on being called a "sex symbol." She added, "'Sex Symbol', 'Hot', what does that even mean? What is a symbol of sex? Kamasutra is a symbol of sex, it's not Esha."

Esha continued, "If you say Esha Gupta is a sex symbol, then this is something God has given me, something Kamdev has given me. If you are calling me a sex symbol, it's not a good title to have. It's not bad either." She then explained how such stereotyping impacted her, revealing that she became very underconfident about her look.

"Because you feel like, 'Oh, I shouldn't look like this, right? I should look like the girl next door.' Because that's what people keep teaching you, that how you look is not good," she mentioned, pointing out how actresses now get surgeries to look like her. The 39-year-old actress also shared that a guy from the industry asked her to get a nose job done, but she chose to remain confident with the way she looked rather than changing anything. As for her work, Esha, who made her debut with Jannat 2, starring Emraan Hashmi, was last seen on screen in Bobby Deol's Aashram. Reportedly, she has been roped in for Dhamaal 4, featuring Ajay Devgn, Riteish Deshmukh, Arshad Warsi, Sanjay Mishra, Jaaved Jaaferi, along with fresh faces like Sanjeeda Shaikh, Anjali Anand and Upendra Limaye. It is slated to hit theatres on Eid 2026.

Gauahar Khan

Offers Duas At Sana Khan's Home After Mother's Demise

Former actress and Bigg Boss 6 fame Sana Khan is going through a rough phase in her life as she lost her mother, Saeeda, on Tuesday, due to prolonged illness. In an emotional post, Sana expressed her profound grief and the deep pain she has been going through. During this time, her close friend and mom-to-be Gauahar Khan, along with her husband Zaid Darbar, arrived at her residence to pay their heartfelt condolences. In a video shared on Instagram, Gauahar, dressed in a white suit, is seen entering the building as her husband follows her. Apart from Gauahar and Zaid, several close friends like comedian Munawar Faruqui's wife Mehzabeen Coatwala were seen visiting Sana's residence to pay their respects and support the grieving family. Sharing an emotional note on Instagram stories, Sana wrote, "Inna Lillahi Wa Inna Ilaih Rajioon, My beloved mother, Mrs Saeeda, has returned to Allah after struggling with bad health conditions. Namaz-e-Janaza will be performed at Oshiwara Qabarsthan after isha salat @9:45. Your prayers for my mother will be helpful." Her mother's funeral and burial ceremony were held on Tuesday night in Mumbai. Sana has always had a strong bond with her mother. In 2023, she shared a heartfelt video of her mother fixing her shoelaces, expressing her respect and

gratitude to her. "No love is more pure and unselfish than a mother's love. Had to post this because we often forget the love and sacrifices they make for us," she wrote. "No matter how old you are, you will always be a chota bacha for them," she added.

Who Is Sana Khan?

Sana rose to fame after her appearance in Salman



Khan's controversial reality show, Bigg Boss 6. She appeared in a number of films including Jai Ho, Wajah Tum Ho, Toilet: Ek Prem Katha and others. In 2020, she announced her departure from showbiz due to religious reasons and has since adopted a spiritual lifestyle. She is now an entrepreneur and mother of a child with husband, Anas Saiyad.

